निष्पादन बजट वर्ष 2018–19

विभाग– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष– संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6 / 6	7	8
1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	शहरी गरीबों को स्वरोजगाार हेतु कार्यक्रमों को संचालित कर हितग्राहियों को क्रियान्वयन हेतु	362991	निम्नाकिंत घटक शहरी गरीबों के लिए क्रियान्वित होगें :- 1. सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास 2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार 3. स्व–स्वरोजगार कार्यक्रम 4. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास 5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता 6. शहरी वेघरों के लिए आश्रय की योजना 7. प्रशासनिक ण्वं अन्य व्यय 8. सूचना सम्प्रेषण मद	1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह गठन– 3780, क्षेत्र स्तरीय संगठन निर्माण–130 तथा शहर स्तरीय संगठन– 12 2. स्व सहायता समूहों को आवर्ती निधि –3340, क्षेत्र स्तरीय संगठन आवर्ती निधि– 123 3. हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण– 10440 4. हितग्राहियों का प्रमाणीकरण– 7986 5. व्यक्तिगत ऋण– 4414 6. समूह ऋण– 292 7. बैंक लिंकेज ऋण– 1793 8. राज्य मिशन प्रबंधक– 6, सिटी मिशन प्रबंधक– 69, सामुदायिक संगठक– 194 तथा सपोर्ट स्टॉफ– 44 9. सर्वेक्षित पथा विक्रेता– 29985, परिचय पत्र वितरण– 22582 10. संचालित आश्रय स्थल– 22, निर्माणाधीन– 20 एवं निविदा प्रक्रियाधीन आश्रय–स्थल– 13	318792	

निष्पादन बजट वर्ष 2018–19

विभाग– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष– संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ			टिप्पणियां
						भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
2.	स्मार्ट सिटी	राजधानी रायपुर का स्मार्ट सिटी के मापदण्ड अनुरूप विकसित करना।	3780000	स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (रिट्रो फिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) के अतिरिक्त पैन सिटी प्रयास, जिसमें शहर के बड़े भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (स्मार्ट सॉल्यूशन) लागू किया जाता है ।		नगर निगम रायपुर, बिलासपुर एवं अटल नगर रायपुर	3480000	
3.	स्वच्छ भारत अभियान	यह केन्द्रीय योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कुल 426637 शौचालय विहित आवास गृहों में से 341310 आवास गृहों में निजी शौचालय 14780 कम्यूनिटी शौचालय एवं 2000 सीटर पब्लिक शौचालय का निर्माण किया जाना है	1580000	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कुल 426637 शौचालय विहित आवास गृहों में से 341310 आवास गृहों में निजी शौचालय 14780 कम्यूनिटी शौचालय एवं 2000 सीटर पब्लिक शौचालय का निर्माण किया जाना है ।	 1. 2.	योजनान्तर्गत सामुदायिक एवं निजी शौचालयों का निर्माण किया गया है :- सामुदायिक शौचालय – कुल 172 ब्लॉक में 1481 सीट, निजी शौचालय – 2018–19 के लिए 135806	1474507	
4.	सबके लिए आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना ''सबके लिए आवास योजना'' के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक के लिये क्रियान्वयन होंगे:-	2341000	वर्ष 2015–2022 तक सभी पात्र परिवारों को 30 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल आकार के अधोसंरचनायुक्त पक्के आवास प्रदान करने के लिए केन्द्राय सहायता का प्रावधान है ।	1.	आईएसएसआर घटक अंतर्गत निर्मित आवास –निरंक	1786606	

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ भौतिक	वास्तविक उपलब्धियाँ वित्तीय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6 6	7	8
		1. झुग्गी बस्ती पुर्नविकास 2. ऋण से जुड़ी व्याज 3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के किफायती आवास का निर्माण 4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवासों का निर्माण		प्रथम श्रेणी के शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए 04 चरणों में क्रियान्वयन किया जाना है ।	2. एएचपी घटक अंतर्गत निर्मित आवास - 3169 3. बीएलसी घटक अंतर्गत निर्मित आवास की संख्या -14431 है। इस प्रकार कुल 17600 आवासों का निर्माण योजनान्तर्गत किया गया है।		
5.	अमृत मिशन	अमृत मिशन हेतु प्रमुख अवरचना घटक निम्नानुसार है:- 1. जलापूर्ति 2. सिवरेज सुविधाएं ओर सेटेज प्रबंधन 3. बाढ़ को कम करने के लिए बर्षा जल नाले 4. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग सील 5. बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्को और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना ।	2310000	राज्य के 09 शहरों-रायपुर, बिलसपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर को अमृत मिशन हेतु चयनित किया गया ।	योजनान्तर्गत प्रदेश के 09 शहर (रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग एवं रायगढ़) की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य प्रगतिरत एवं 02 शहर (रायपुर एवं राजनागदंगांव) में सीवरेज मैनेजमेंट परियोजना का कार्य प्रगतिरत तथा प्रत्येक 09 शहरों (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं रायगढ़) में उद्यान विकास कार्य	2310000	-

निष्पादन बजट वर्ष 2018-19

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018-19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियॉं		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5 6	6	7	8
6.	झुग्गी झोपड़ी पेयजल तथा शौचालय निर्माण	गंदी बस्ती क्षेत्रों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना	94100	नगरीय निकायों में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था	168 नगरीय निकाय	94100	निकायों को पेयजल शौचालय व्यवस्था हेतु आबंटन
7.	वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	नगरीय निकायों में स्वच्छ पेयजल प्रदाय किया जाना है ।	100000	168 निकाओं में आवश्यकतानुसार वॉटर ए. टी.एम. की स्थापना	12 नगरीय निकायों में 91 नग वाटर ए.टी.एम की स्थापना	61000	
8.	मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय निकायों को कार्ययोजना अनुसार पेयजल, प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय साफ सफाई एवं सामुदायिक भवन आदि के लिए अनुदान	720500	168 नगरीय निकायों के लिए निम्नाकिंत कार्य योजना है:- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. ठोस अवशिष्ट सामग्री कय प्रबंधन	168 नगरीय निकाय	720500	

निष्पादन बजट वर्ष 2018–19

विभाग– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष– संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स		वास्तविक उपलब्धियाँ		टिप्पणियां
						भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	6	7	8
9.	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन	राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चालू होने से राज्य के 141 नगरीय निकाय के कुल बीपीएल जनसंख्या 9,74,166 जिसमें 2,35,387 गरीब परिवारों का आजीविका, कौशल उन्नयन तथा जमीनी स्तर के संस्थाआ के निर्माण गतिविधियों से वंचित हो जायेंगे जिसकी पूर्ति के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन नवीन योजना लागू किया जावेगा ।	400	राज्य के 141 नगरीय निकाय के कुल बीपीएल जनसंख्या 9,74,166 जिसमें 2,35,387 गरीब परिवारों का आजीविका तथा जमीनी स्तर के संस्थाओं के निर्माण गतिविधियों से वंचित हो जायेंगे जिसकी पूर्ति के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन नवीन योजना लागू किया जावेगा ।		निरंक		
10.	विशिष्ट प्रयोजनार्थ अनुदान	योजनांतर्गत नगरीय निकायों को अन्य विकास कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान निश्चित अनुपात में स्वीकृत किया जाता है ।	650000	नगरीय निकायों द्वारा तैयार विकास की योजनाओं हेतु तैयार प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना में नगर निगम हेतु 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान तथा नगर पालिका पंचायत हेतु 60 प्रतिशत ऋण एवं 40 प्रतिशत अनुदान का अनुपात निर्धारित है		निरंक		

निष्पादन बजट वर्ष 2018–19

विभाग– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विभागाध्यक्ष– संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2018–19	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियाँ भौतिक	वास्तविक उपलब्धियाँ वित्तीय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5 6	6	7	8
11.	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराना	1350	जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएगें।	निरंक		
12.	नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास योजना	नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु अनुदान एवं ऋण	5757050	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान राशि की मांग की गई है जिसमें अंतर्गत निम्नानकित कार्य प्रमुखतः से किया जाना है । 1. मास्टर प्लान/सी.डी.पी के मुख्य मार्ग 2. फ्लाई ओव्हर निर्माण 3. मल्टी लेवर पार्किग स्थल निर्माण 4. पशु वंध गृह निर्माण 5. नगरीय जल प्रदाय योजना 6. स्पोटर्स काम्पलेक्स 7. बिलासपुर/रायपुर में फ्लाई ओव्हर निर्माण 8. नगरीय निकायो में हाईटेक बस स्टैण्ड का निर्माण 9. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कामकाजी महीला छात्रावास का निर्माण	168 नगरीय निकाय	2277050	